

प्रेषक,

भास्करानन्द,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
टिहरी गढ़वाल।

राजस्व अनुभाग-2

दहरादून: दिनांक, 20 अक्टूबर, 2014

विषय:- जनपद टिहरी गढ़वाल में टिहरी मेंगा पर्यटन सर्किट, टिहरी एडवेन्चर सेन्टर, मल्टी प्रपज हॉल एवं हेलीपोर्ट के निर्माण हेतु कुल 23.208 हैं भूमि पर्यटन विभाग, उत्तराखण्ड शासन को निःशुल्क हस्तांतरण किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1928/11-128(2013-14) दि-03-07.2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, जनपद एवं तहसील टिहरी की पट्टी अदूर के ग्राम कोटी के खाता सं-6/170 के खसरा सं-13/0.976 हैं, 1266/3.548 हैं, 1315/1.292 हैं, ग्राम गाजणा के खाता सं-01 के 11/0.461 हैं, 22/0.892 हैं, 32/2.258 हैं, 313/1.675 हैं, 315/0.100 हैं तथा पट्टी सारज्यूला के ग्राम बागी के खाता सं-66 के खसरा सं-1114/4.438 हैं, 1115/1.703 हैं, 1116/0.722 हैं, 1118/0.692 हैं, 1121/2.447 हैं, 1122/0.560 हैं, खाता सं-16 के खसरा सं-1117/0.105 हैं, खाता सं-25 के खसरा सं-1119/0.015 हैं तथा खाता सं-14 के खसरा सं-1120/1.324 हैं। इस प्रकार तीन ग्रामों की कुल 23.208 हैं, श्रेणी 9(3)ड कृषि योग्य बंजर भूमि को वित्त अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-260/वित्त अनुभाग-3/ 2002 दिनांक 15-02-02 के प्राविधानों के अधीन तथा पर्यटन विभाग, उत्तराखण्ड शासन की सहमति/अनापत्ति के क्रम में पर्यटन विभाग, उत्तराखण्ड शासन को निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन निःशुल्क हस्तान्तरित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (1) भूमि पर कोई धार्मिक अथवा ऐतिहासिक महत्व की इमारत न हो।
- (2) जिस परियोजना के लिए भूमि हस्तान्तरित की जा रही है वह एक अनुमोदित परियोजना हो और उसके लिए शासन से सहमति प्राप्त हो चुकी हो।
- (3) हस्तान्तरित भूमि यदि प्रस्तावित कार्य से भिन्न प्रयोजन के लिए उपयोग की जाये तो उसके लिये मूल विभाग से पुनः अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
- (4) यदि भूमि की आवश्यकता न हो या 3 वर्षों तक हस्तान्तरित भूमि प्रस्तावित कार्य के लिए उपयोग में नहीं लायी जाती है तो वह मूल विभाग में स्वतः ही निहित हो जायेगी।
- (5) जिस प्रयोजन हेतु भूमि हस्तान्तरित की जा रही है उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु किसी अन्य व्यक्ति, संस्था, समिति अथवा वभाग आदि को मूल विभाग की सहमति के बिना भूमि हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।
- (6) जिस प्रयोजन हेतु भूमि आवंटित की जा रही है उसकी पूर्ति के उपरान्त यदि भूमि अवशेष पड़ी रहती है, तो मूल विभाग को उसे वापस लेने का अधिकार होगा।

- (7) प्रश्नगत भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम लागू होने की दशा में भूमि के उपयोग का परिवर्तन गैर वानिकी कार्य हेतु तभी अनुमन्य होगा जब उक्त अधिनियम के अन्तर्गत नियत प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर ली जायेगी।
- (8) प्रश्नगत नॉन जेड०४० भूमि आवंटन के पूर्व जर्मीदारी विनाश एवं भू-सुधार अधिनियम की धारा-132 के समकक्ष एवं अन्य सुसंगत प्राविधानों का अनुपालन जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
- (9) इस संबंध में सिविल अपील संख्या-1132/2011 (एस०एल०पी०)/(सी) संख्या-3109/2011 श्री जगपाल सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य में मा० सर्वोच्च न्यायालय के आदेश एवं अन्य संगत निर्देशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (10) आवंटन की अवधि समाप्त होने अथवा उपरोक्त शर्तों बिन्दु संख्या-1 से 09 मे से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में प्रश्नगत भूमि निर्माण सहित राजस्व विभाग में निहित हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।

कृपया इस संबंध में नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में जिला स्तर से निर्गत आदेश एवं इस शासनादेश की शर्तों के अनुपालन स्थिति से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(भास्करानन्द)
सचिव।

प०प०संख्या-2287/समदिनांकित/2014

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1— सचिव, पर्यटन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 2— आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 3— आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
- 4— निदेशक, एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 5— गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
2/9
(संतोष बडोनी)
उप सचिव।